

126 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

[2023] 10 एस. सी. आर 126:2023 आई. एन. एस. सी. 594

/

धीरज सिंह

बनाम

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ओआरएस।

(2023 की सिविल अपील संख्या 4172) 04 जुलाई, 2023

/

[कृष्णा मुरारी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे।]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-ओ. 41,आर. 22-मुआवजे में वृद्धि के लिए अपीलार्थियों द्वारा दायर क्रॉस आपत्तियां, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया-आयोजित:क्रॉस आपत्तियाँ, एक नियमित अपील के विपरीत, पहले से मौजूद अपील के भीतर दायर की जाती हैं-हालाँकि, O. 41 के अनुसार,आर. 22, परस्पर आपत्तियों में नियमित अपील के सभी निहितार्थ होते हैं और इसलिए, उसी पर निर्णय देने वाले न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए-अपील न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपने समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों पर अपना दिमाग लगाए और ऐसे मामलों में जहां उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहता है, मामले को नए निर्णय के लिए उसी न्यायालय में भेजा जाना चाहिए-वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी परस्पर आपत्तियों में उठाए गए मुद्दों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था-जबकि, उच्च न्यायालय ने अपील में उठाए गए अन्य सभी मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण किया और दोनों निचली अदालत के आदेश, विशेष रूप से परस्पर आपत्तियों पर कोई चर्चा नहीं हुई, बहुत अंतर्गत उल्लेख भी-उच्च न्यायालय ऐप द्वारा दायर परस्पर आपत्तियों पर विचार करने के लिए बाध्य था।4(1), 6, 17,18.

/

/

/

/

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-ओ. 41,आर. 22-आयोजित:ऐसे मामलों में जहां डिक्री आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में है, लेकिन आंशिक रूप से प्रतिवादी के खिलाफ भी है, O. 41 के भीतर दो उपचार,आर. 22 प्रत्यर्थी के पास अपनी क्रॉस आपत्तियां दायर करने और पूरी तरह से डिक्री का समर्थन करने के लिए रहता है-विधि में तीसरा उपाय इस तरह से निर्धारित

सीमा अवधि के भीतर एक क्रॉस अपील दायर करने का अधिकार है, जो संक्षेप में अपने आप में एक अलग अपील है, जो दूसरे पक्ष द्वारा दायर अपील से स्वतंत्र, मूल डिक्री के हिस्से या पूरे को चुनौती देती है-प्रत्यर्थी को निचली न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री का पूरी तरह से समर्थन करने का भी अधिकार है।

/

/

126

127

धीरज सिंह बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और हमारा।

/

संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (मृत) एल. आर. (2001) 2 एससी 407; मधुर और अन्य। बनाम।संग्राम और

ओआरएस। (2001) 4 एससीसी 756:[2001] 3 एससीआर 138; जितेंद्र

प्रसाद नायक बनाम अनंत कुमार साह और अन्न। **(1998) 9**

एस. सी. सी. **383**-पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

/

(2001) 2 एससी 407

पर विश्वास किया

पैरा **19**

[2001] 3 एससीआर 138

पर विश्वास किया

पैरा **20**

(1998) 9 एस. सी. सी. 383

पर विश्वास किया

पैरा **21**

/

सिविल अपील की अधिकारिता 2023 की सिविल अपील सं. 4172।

सी. ए. संख्या शून्य/2023 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 05.01.2017 से।

सह

/

2023 की सिविल अपील सं. 4174, 4173, 4176 और 4177। एस. के. पत्री, हरप्रसाद साहू, सुश्री वेलास्री एस., श्रीमती किरण मोहंतो, संजय कुमार मिश्रा, प्रणय कुमार महापात्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

/

रवींद्र कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, बिनय कुमार दास, सुश्री प्रियंका दास, सुश्री नेहा दास, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

/

देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. वर्तमान अपील इलाहाबाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश और दिनांक (आई. डी. 1) के निर्णय के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।

/

तथ्य

4. वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए आवश्यक प्रासंगिक तथ्य, सुविधा के लिए, उत्तर प्रदेश की प्रतिवादी राज्य सरकार ने धारा 17 के साथ धारा 4 (1) के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की थी।

/

/

[2023] 10 एस सी आर।

/

आई. डी. 1 पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ग्रेटर नोएडा के उद्देश्य के लिए अपीलार्थियों की भूमि सहित भूमि का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया गया था। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उक्त भूमि की घोषणा 25.06.1993 पर जारी की गई थी, और उपरोक्त भूमि का कब्जा 13.08.1993 और 31.05.1994 के बीच अलग-अलग तिथियों पर लिया गया था। 5. उक्त भूमि के अधिग्रहण के बाद, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा भूखंडों का बाजार मूल्य तीन अलग-अलग दरों पर निर्धारित किया। 32.52-/-, रु। 22.44-/- और रु। 16.46-/- पैसा प्रति वर्ग गज।

/

6. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ की मांग की और मुआवजे का दावा किया। 350/- से रु। 500/- प्रति वर्ग गज आसपास के क्षेत्र में अधिग्रहित अन्य भूमि के साथ समानता के आधार पर। विद्वान जिला न्यायाधीश ने, उपरोक्त संदर्भ में, अपने दिनांकित 09.05.2002 के निर्णय के माध्यम से, उक्त भूमि का बाजार मूल्य रु। 400/-, लेकिन विकास शुल्क के लिए एक तिहाई राशि काट ली, और बाजार मूल्य रु। 267/- प्रति वर्ग गज और रु। 9 प्रतिशत और 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रति वर्ग गज के हिसाब से 80 रुपये और कब्जे के हस्तांतरण की तारीख से बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजा।

/

/

7. इसके खिलाफ, प्रतिवादी ग्रेटर नोएडा ने उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की, जिस पर अपीलकर्ताओं ने आगे वृद्धि की मांग करते हुए अपनी प्रति अपील दायर की।

/

8. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने आदेश और दिनांक 04.01.2017 के निर्णय के माध्यम से, विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित मुआवजे की पुष्टि की। अपीलार्थियों का यहाँ यह तर्क है कि उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय उनके द्वारा दायर क्रॉस आपत्तियों पर विचार नहीं किया।

/

9. अपीलार्थी, इस तथ्य से व्यथित थे कि वृद्धि के लिए उनकी प्रति-आपत्ति पर ठीक से विचार नहीं किया गया था, उन्होंने एक समीक्षा दायर की, हालाँकि, इसे आक्षेपित आदेश और दिनांक

05.01.2017 के निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान विशेष अनुमति याचिका।

/

10. स्पष्टता के लिए, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भूमि अधिग्रहण को वर्तमान अपीलों के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा रही है, और सीमित चुनौती केवल उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे की मात्रा तक ही सीमित है।

/

129

धीरज सिंह बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक

विकास प्राधिकरण और ओआरएस। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

/

11. हाथ में मौजूद मुद्दे की सराहना करने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का विश्लेषण करना चाहिए, यह देखने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर क्रॉस आपत्तियों पर कोई विचार किया गया है, और यदि इस तरह के विचार को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो यह न्यायालय किस हद तक राहत दे सकता है।

/

विश्लेषण

12. आदेश 41 नियम 22, जो वर्तमान मामले में शासी विधि है, पहली अपील की न्यायालय में एक प्रतिवादी के लिए उपलब्ध उपचारों के बारे में विस्तार से बताता है जहां एक मूल डिक्री को चुनौती दी गई है। हमारी राय में, वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के लिए उक्त प्रावधान का विश्लेषण आवश्यक है।

/

13. ऐसे मामलों में जहां पहली बार की न्यायालय द्वारा पारित डिक्री पूरी तरह से प्रतिवादी के पक्ष में है, ऐसी परिस्थिति में, इस तरह की डिक्री की अपील करने के लिए प्रतिवादी के पक्ष में कोई उपाय मौजूद नहीं है, क्योंकि अपील करने का कोई अधिकार किसी पक्ष को निहित नहीं किया जा सकता है, जो सफल है।

/

14. हालांकि, ऐसे मामलों में जहां पहली बार न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में है, लेकिन आंशिक रूप से प्रतिवादी के खिलाफ भी है, आदेश 41 नियम

22 के भीतर दो उपाय प्रतिवादी के पास रहते हैं, जो हैं (i) अपनी क्रॉस आपत्तियां दायर करना और (ii) पूरी तरह से डिक्री का समर्थन करना। विधि में एक तीसरा उपाय भी मौजूद है, जो एक क्रॉस अपील दायर करने का अधिकार है, जिस पर भी संक्षेप में चर्चा की जाएगी।

/

15. ऐसे मामलों में जहां विरोधी पक्ष मूल डिक्री के हिस्से या पूरे के खिलाफ पहली अपील दायर करता है, और उक्त पहली अपील में प्रतिवादी, डिक्री का हिस्सा या पूरा उनके पक्ष में होने के कारण, पहली बार में अपील दायर करने से दूर रहता है, ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिवादी को सुनवाई का उचित मौका भी दिया जाता है, उसे दूसरे पक्ष द्वारा पहले से ही इस तरह से स्थापित अपील के भीतर अपनी क्रॉस आपत्तियां दायर करने का अधिकार दिया जाता है, न केवल दूसरे पक्ष द्वारा उठाए गए तर्कों के खिलाफ, बल्कि पहली बार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के हिस्से या पूरे के खिलाफ भी।

/

/

16. इसी तरह की परिस्थिति में, जहां दूसरे पक्ष ने पहली बार में एक अपील को प्राथमिकता दी है, प्रति-आपत्तियों के उपचार के अलावा, प्रतिवादी भी सीमा के भीतर एक प्रति-अपील दायर कर सकता है।

/

/

/

[2023] 10 एस सी आर।

इस प्रकार निर्धारित अवधि, जो संक्षेप में अपने आप में एक अलग अपील है, जो दूसरे पक्ष द्वारा दायर अपील से स्वतंत्र, मूल डिक्री के हिस्से या पूरे को चुनौती देती है। प्रतिवादी को निचली न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री का पूरा समर्थन करने का भी अधिकार है।

17. वर्तमान मामले में, यहाँ अपीलकर्ताओं ने पहली अपील के न्यायालय में एक प्रति-आपत्ति दायर की। इसमें अपीलार्थियों का दावा है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करते समय उनकी प्रति-आपत्ति पर विचार नहीं किया गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि क्रॉस आपत्तियां, एक नियमित अपील के विपरीत, पहले से मौजूद अपील के भीतर दायर की जाती हैं, हालांकि, सी. पी. सी. के आदेश 41 नियम 22 के अनुसार, क्रॉस आपत्तियों में एक नियमित अपील के सभी अंश होते हैं, और इसलिए, उसी पर निर्णय देने वाले न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए।

/

/

18. आक्षेपित आदेश के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थियों द्वारा अपनी परस्पर आपत्तियों में उठाए गए मुद्दों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। उक्त निर्णय में अपीलार्थियों द्वारा दायर क्रॉस आपत्तियों का कोई उल्लेख नहीं पाया गया है। जबकि उच्च न्यायालय ने अपील में उठाए गए अन्य सभी मुद्दों और निचली अदालत के दोनों आदेशों का विस्तृत विश्लेषण किया है, हालांकि, विशेष रूप से क्रॉस आपत्तियों पर कोई चर्चा नहीं होती है, यहां तक कि एक उल्लेख भी नहीं मिलता है।

/

19. संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी के मामले में

/

(मृत) एलआर द्वारा। 1, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपील न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपने समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों पर अपने दिमाग को लागू करे, और ऐसे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, उसे उठाए गए ऐसे सभी मुद्दों के खिलाफ अपने निष्कर्ष भी दर्ज करने चाहिए। सुविधा के लिए, उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ निकाला जा रहा है:

/

“अपीलीय न्यायालय के पास निचली विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र है। पहली अपील पक्षों का एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक कि विधि द्वारा प्रतिबंधित न हो। पूरा मामला तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर पुनः सुनवाई के लिए खुला है। इसलिए, अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपने विवेकपूर्ण प्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए, और दलीलों के साथ उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर कारणों द्वारा समर्थित निष्कर्षों को दर्ज करना चाहिए, और पक्षकारों द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।

/

1 (2001) 2 एससी 407 ए

/

131

धीरज सिंह बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक

विकास प्राधिकरण और ओआरएस। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

तथ्य के निष्कर्ष को उलटते समय अपीलीय न्यायालय को निचली विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क के साथ निकटता से आना चाहिए और फिर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने स्वयं के कारण निर्धारित करने चाहिए। यह न्यायालय को एक और अपील की सुनवाई करते हुए संतुष्ट करेगा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उससे अपेक्षित कर्तव्य का निर्वहन किया था। "

/

20. मधुर और ओआरएस के मामले में। बनाम संग्राम और अन्य। 2,

इस न्यायालय ने संतोष हजारी निर्णय (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि प्रथम अपील की अदालत का कर्तव्य है कि वह अपने समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों पर अपने निष्कर्ष दर्ज करे और ऐसे मामलों में जहां उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहता है, मामले को नए निर्णय के लिए फिर से उसी अदालत में भेजा जाना चाहिए।

/

21. इसके अलावा, जितेंद्र प्रसाद नायक बनाम अनंत के मामले में।

कुमार साह और अन्न। 3, इस न्यायालय ने एक ऐसी ही परिस्थिति में, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर प्रति-आपत्तियों पर प्रथम अपील न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था, अभिनिर्धारित किया कि मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया और निम्नानुसार टिप्पणी की गई:

/

".....मान लीजिए, बेदखली के दो आधारों में से एक के अस्तित्व की पहली अपीलीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृति के खिलाफ अपीलार्थी-मकान मालिक द्वारा एक प्रति-आपत्ति दायर की गई थी। तथापि, दूसरे आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थी-किरायेदार की अपील का निर्णय करते समय, उच्च न्यायालय द्वारा प्रति-आपत्ति का अस्तित्व इस परिणाम के साथ छूट गया प्रतीत होता है कि प्रति-आपत्ति पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। इसलिए, इस कारण से आक्षेपित निर्णय को अन्य बातों के साथ-साथ कायम नहीं रखा जा सकता है। हमारी यह भी राय है कि वास्तविक आवश्यकता के आधार के अस्तित्व से संबंधित प्रश्न, जो किरायेदार के पक्ष में तय किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा किराए के भुगतान में चूक से संबंधित अन्य बिंदु के साथ एक नए निर्धारण की आवश्यकता है, जो प्रति-आपत्ति का विषय था।

/

/

/

22. उपर्युक्त चर्चाओं और निर्णयों को, जब वर्तमान मामले को संदर्भित किया जाता है, तो यह पता चलता है कि उच्च न्यायालय

2 (2001) 4 एससीसी 756 3 (1998) 9 एससीसी 383

/

132

/

[2023] 10 एस सी आर।

इसअंतर्गत अपीलार्थियों द्वारा दायर क्रॉस आपत्तियों पर विचार करने का दायित्व था।चूंकि अपील में निर्णय पारित करते समय इस तरह के दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया था, इसलिए हमारी यह सुविचारित राय है कि यह मामला अपीलकर्ताओं द्वारा अपील के दौरान प्रति आपत्तियों में उठाए गए आधारों पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में रिमांड के लिए उपयुक्त है।तदनुसार, वर्तमान अपीलों को इस हद तक अनुज्ञात जाती है।

/

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/